



भारत में उच्च शिक्षा एवं चुनौतियाँ

हरिओम मद्देशिया

शोध छात्र

डा० हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर, म०.प्र०.

पवन साहू

शोध छात्र

डा० हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर, म०.प्र०.

प्रस्तावना:

भारत में शिक्षा के प्रति रुझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। प्राचीनकाल में गुरुकुलों, आश्रमों तथा बौद्ध मठों में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था होती थी। तत्कालीन शिक्षा केन्द्रों में नालंदा, तक्षशिला एवं वल्लभी की गणना की जाती है। मध्यकाल में उच्च शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मुगल शासकों ने दिल्ली, अजमेर, लखनऊ एवं आगरा में मदरसों का निर्माण कराया। भारत में आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल से हुई। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम सन् 1981 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। सन् 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने "एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल" की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया। सन् 1813 के चार्टर्ड एक्ट में सर्वप्रथम भारतीयों के शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी, जिसको भारत में साहित्य के पुनः विकास के लिए एवं स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च करने की बात कही गयी थी किन्तु भारतीय विद्वान व साहित्य शब्द की सही व्याख्या नहीं होने के कारण प्राच्य व पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया। प्राच्य व पाश्चात्य विवाद को सुलझाने के लिए लार्ड आर्कलैंड ने टी. वी. मैकाले के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। जिसने शिक्षा के अधोमुखी निरस्यन्दन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा को उच्च वर्गों के माध्यम से निम्न वर्गों तक पहुँचाने की बात की गयी थी। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार साथ साथ ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रूप से भारतीय हो पर विचारों, रुचि व बुद्धि से अंग्रेज हो। भारत के साहित्य के विषय में मैकाले का कहना है कि "यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का तख्ता, भारत तथा अरब के समस्त साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है" 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों पर व्यापक विचार किया गया था।



इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का "मैग्ना कार्टा" भी कहा जाता है। इसी घोषणा पत्र की सिफारिश पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित किये गए। 1899 में जब लार्ड कर्जन भारत का वायसराय बना तो उसने लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना की उसने कहा कि "मैकाले की नीति देशी भाषाओं के विरुद्ध है" तथा सितम्बर 1901 में कर्जन के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की, 1902 में टामस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। समिति की सिफारिश के अनुसार कर्जन ने सन् 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। सन् 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए डॉ० माइकल सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, इस आयोग का गठन केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था किन्तु आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा पर भी अपने विचार व्यक्त किया साथ ही आयोग के 1904 ई. के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी शब्दों में निंदा की। आजादी के बाद उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने सन् 1948 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय के विकास हेतु अपनी रिपोर्ट देनी थी। अगस्त 1949 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसकी मुख्य सिफारिशों में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने सुझाव दिया गया था तथा विश्वविद्यालय के देख रेख तथा विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात कही थी। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने सन् 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, सन् 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा इस आयोग को स्वायत्तपूर्ण परिनियम पद दे दिया गया।

आजादी के बाद सन् 1951 में देश की साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी तथा आज लगभग 69 वर्षों बाद साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत तो हुई किन्तु इसके साथ ही साक्षर बेरोजगारों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव को दर्शाता है। भारत छात्रों की संख्या की दृष्टि से अमेरिका व चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। फिर भी हाल ही में जारी क्यू और एस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम 200 संस्थानों में भारत का कोई भी शिक्षण संस्थान स्थान नहीं बना पाया है। उच्च शिक्षा की स्थिति यह है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 9 छात्रों में से केवल 1 छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। नैसकाम और मैकिन्से के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में से मानविकी में 10 में से 1 तथा इंजीनियरिंग में 4 में से 1 भारतीय छात्र ही रोजगार के योग्य है। हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति यह है कि अधिकतम संस्थान शिक्षकों के अभाव से ग्रसित हैं। आई. आई.टी. जैसे संस्थानों में 15-25 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। उच्च शिक्षा की एक प्रमुख कमी बताते हुए पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति नरेन्द्र जाधव ने कहा कि कई विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले तीस वर्षों



से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव ही नहीं किया गया है। हालांकि सन् 2013 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा “राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” का प्रारम्भ किया गया किन्तु ये प्रयास काफी नहीं हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। इस दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। इसके लिए साक्षर ही नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो वर्तमान उच्च शिक्षा में सुधार से ही संभव हैं।

यदि भारत को सन् 2020 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है तो हमें गरीबी, बेरोजगारी व निरक्षरता जैसे अभिशाप को दूर करना ही होगा जो उच्च शिक्षा के द्वारा ही संभव होगा, इसी को ध्यान में रखकर शोधकर्ता द्वारा “भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति का एक अध्ययन” विषय का चयन किया गया है।

उद्देश्य –

शोधार्थी द्वारा अभी हाल ही में उच्च शिक्षा पर बनाये गए एनोटेड बिब्लिओग्राफी में उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षण, शोध, शिक्षक प्रशिक्षण, परीक्षा प्रणाली आदि का अध्ययन किया गया है जो वर्तमान उच्च शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं इसी व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इस विषय का चयन किया गया है। जिसका उद्देश्य निम्न है—

1. उच्च शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

सम्बंधित साहित्य का सर्वेक्षण

शोधकर्ता की सफलता के लिए विषयवस्तु से सम्बंधित साहित्य एवं सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र में अब तक किये गये कार्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। सम्बंधित साहित्य के अध्ययन से शोध समस्या की गहरी एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि विकसित होती है और समस्या तथा अनावश्यक श्रम की पुनरावृत्ति से बचाव होता है। अतः अनुसंधानकर्ता को अपने विषय वस्तु से सम्बंधित साहित्य का व्यापक ज्ञान होना आवश्यक होता है।

गुडवार एवं स्केटस के अनुसार : “एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहे औषधि सम्बंधित आधुनिकतम खोजों से परिचित होता रहे। उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र, अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले शोधार्थी तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बंधित खोजों से परिचित होना आवश्यक है।”



सम्बंधित साहित्य के उपरोक्त महत्व को देखते हुए प्रस्तुत शोध में ऐसे सम्बन्ध साहित्य का अध्ययन किया गया है जो विभिन्न व्यक्तियों तथा शिक्षाविदों द्वारा अनुसन्धान करके प्राप्त किया गया है।

कुमार, अमरदीप (2014): उच्च शिक्षा की पहुँच में बाधाएं और समता के अवसर बिहार के महादलितों का केश अध्ययन. परिप्रेक्ष्य, 21(3), 85–100. ने उच्च शिक्षा में महादलित की पहुँच में बाधा को एक कारण बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अभाव है तथा वंचित तबकों द्वारा उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण महाविद्यालय अपना नामांकन आधार प्रतिशत बढ़ाते जा रहे हैं जिसके कारण सिर्फ शहरी एवं आर्थिक रूप से बेहतर छात्र ही प्रवेश पाते हैं। ज्यादातर महादलित ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, प्रतिभा आधारित नामांकन प्रक्रिया उनके लिए प्रतिकूल है। अतः नामांकन जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने की आवश्यकता तथा साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह 'विद्यार्थी सेवा केन्द्र' राज्य विश्वविद्यालय में खोला जाय, जिससे छात्रों की मदद हो सके।

त्रिपाठी, विवेकनाथ (2013): उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की राजनैतिक संलिप्तता के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। जबकि संलिप्तता के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। छात्रसंघ चुनाव के पक्ष में अधिकांश शिक्षकों ने यह कहा कि अर्थ का ध्यान रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया को परिवर्तित कर देना चाहिए तथा विद्यार्थियों को राजनीति में नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर सम्मिलित होना चाहिए। छात्रसंघ चुनाव का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में परिणाम यह बताते हैं कि छात्रसंघ का शैक्षिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जबकि विद्यार्थी इसके पक्ष में हैं।

सिंह, जे.डी., लाल, रोशन (2013): महाविद्यालयी शिक्षकों के वृत्तिक विकास में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका परिप्रेक्ष्य, 20(2), 93–106 में शोधार्थी द्वारा यह माना गया कि महाविद्यालयी शिक्षकों के वृत्तिक विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षक सूचना एवं संचार तकनीकी की सहायता से अधिक आसानी से अपने वृत्तिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। महाविद्यालयी महिला एवं पुरुष शिक्षकों के वृत्तिक विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका में सार्थक अंतर पाया गया। पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षकों के वृत्तिक विकास में सूचना एवं संचार तकनीकी की सहभागिता कम पाई गयी।

यादव, सी.डी., चरन, अर्चना (2011): वित्तपोषित एवं अनुदानित प्रशिक्षण महाविद्यालयों के छात्र/छात्रा अध्यापकों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन शोध संचयन, 1(1 और 2), 1–6. में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि स्ववित्तपोषित एवं अनुदानित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में धार्मिक मूल्य का विकास एक समान रूप से हुआ है,



अनुदानित महाविद्यालयों के अपेक्षा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के अपेक्षा अनुदानित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में प्रजातान्त्रिक मूल्य व सौन्दर्यात्मक मूल्य अधिक विकसित हुए।

छेवगन, प्रवीन, यादव, रीना. (2011) स्नातक स्तर पर सत्त एवं वार्षिक मूल्यांकन पद्धति का प्रभाव. शोध संचयन, 18(3), 47–64 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि सत्त मूल्यांकन पद्धति एवं वार्षिक मूल्यांकन पद्धति में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समय व्यवस्थापन, स्मृति तथा अध्ययन के आदतों में सार्थक अंतर पाया गया है। दयालबाग विश्वविद्यालय के छात्रों में मध्यमान अंक समय व्यवस्थापन, अध्ययन की भौतिक अवस्थाए, वाचन की क्षमता सम्बन्धी अध्ययन आदतों में आगरा विश्वविद्यालय के छात्रों की अपेक्षा अधिक है, परन्तु अवलोक ग्रहण करना सम्बन्धी अध्ययन में कम है।

गौड़, अष्वनी कुमार (2010): स्ववित्तपोषित अध्यापक संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण-अभिवृत्ति, आत्म-प्रत्यय एवं जीवन मूल्यों पर अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव. परिप्रेक्ष्य, 17(1), 75–90. में शोधकर्ता ने अध्यापकों के शिक्षण अभिवृत्ति, आत्म प्रत्यय एवं जीवन मूल्यों पर अध्ययन करने के पश्चात यह कहा कि प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिवृत्तियों एवं आत्मप्रत्यय के मध्य उच्च धनात्मक सम्बन्ध दृष्टगत हुआ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रशिक्षण पूर्व की तुलना में प्रशिक्षण पश्चात की स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव से स्ववित्तपोषित संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिवृत्ति एवं आत्म प्रत्यय में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। प्रशिक्षण के प्रभाव से ज्ञानात्मक एवं देश भक्ति समर्थ एवं धार्मिक मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है।

अनुसन्धान विधि :

प्रस्तुत शोध कार्य “भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति एवं चुनौतियां” में वर्तमान शिक्षा की स्थिति-परिस्थिति का सही चित्रण करने का प्रयास किया गया है। अतः इस अनुसन्धान में वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

वर्णनात्मक शोध :

किसी विषय, वस्तु या घटना, व्यक्ति की विशेषता और स्थिति, परिस्थिति का सही चित्रण करने के लिये किये जाने वाले शोध को वर्णनात्मक शोध कहते हैं।

प्रस्तुत शोध में समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता द्वारा आकड़ों का चयन द्वितीयक स्रोत से किया गया है। जिसके लिए यू0.जी0.सी0.ए0सी0.इन तथा एम0.एच.आर.डी0.जीओवी.इन व भारतडिक्सनरी.काम का प्रयोग किया गया है।



ऑकड़ों का चयन व विश्लेषण :

स्वतंत्रता के समय उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति—

तालिका संख्या 01

वर्ष	विश्वविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या
1947	20	500	2.1 लाख
31.03.2013	711	40760	2,65,85,437 (265.9 लाख)

स्रोत : यूजीसी0 एनुअल रिपोर्ट 2014-15

- स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 20 विश्वविद्यालय, 50 महाविद्यालय तथा छात्रों की संख्या 2.1 लाख थी
- वही 31 मार्च 2015 तक भारत में कुल 711 विश्वविद्यालय तथा 40760 महाविद्यालय तथा कुल छात्रों की संख्या 2,65,85,437 (265.9 लाख) हो गयी

यदि हम इन आंकड़ों का अध्ययन करें तो—

- सन् 1947 में कुल विश्वविद्यालय केवल 20 थे तथा उस समय साक्षरता दर लगभग 18 प्रतिशत थी
- वही वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संख्या में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई
- जबकि साक्षरता दर में केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई

वही यदि छात्रों के नामांकन के दृष्टिकोण को देखा जाये तो सन् 1947 में उच्च शिक्षा में पंजीकृत छात्रों की संख्या 2.1 लाख तथा आज 31 मार्च 2015 को पंजीकृत छात्रों की संख्या 2,65,85,437 (265.9 लाख) हो गयी।

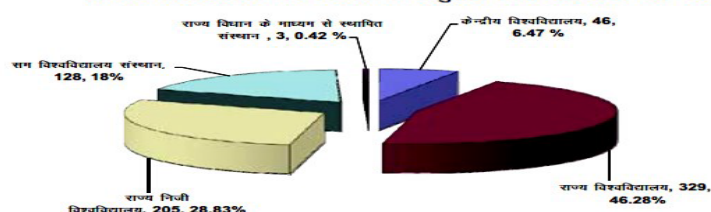
तालिका संख्या 02

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की स्तरवार संख्या

क्र. सं.	संस्थान का स्वरूप	संस्थानों की संख्या (31.03.2015 की स्थिति के अनुसार)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	46
2.	राज्य विश्वविद्यालय	329
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	205
4.	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	3
5.	सम विश्वविद्यालय संस्थान	128
6.	कुल	711
	महाविद्यालय	40760*

* अनतिम

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की स्वरूपवार संख्या



स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



उपरोक्त पाई चार्ट का अध्ययन करने के पश्चात यह पता चलता है कि भारत जैसे देश जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हैं।

- जहाँ 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या पर मात्र 46 केन्द्रीय विश्वविद्यालय जो कुल विश्वविद्यालय का मात्र 6.4 प्रतिशत हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं।
- 329 राज्य विश्वविद्यालय यह कुल विश्वविद्यालय का मात्र 46.28 प्रतिशत हैं।

हमारे देश की आधी आबादी इन विश्वविद्यालयों पर आश्रित हैं।

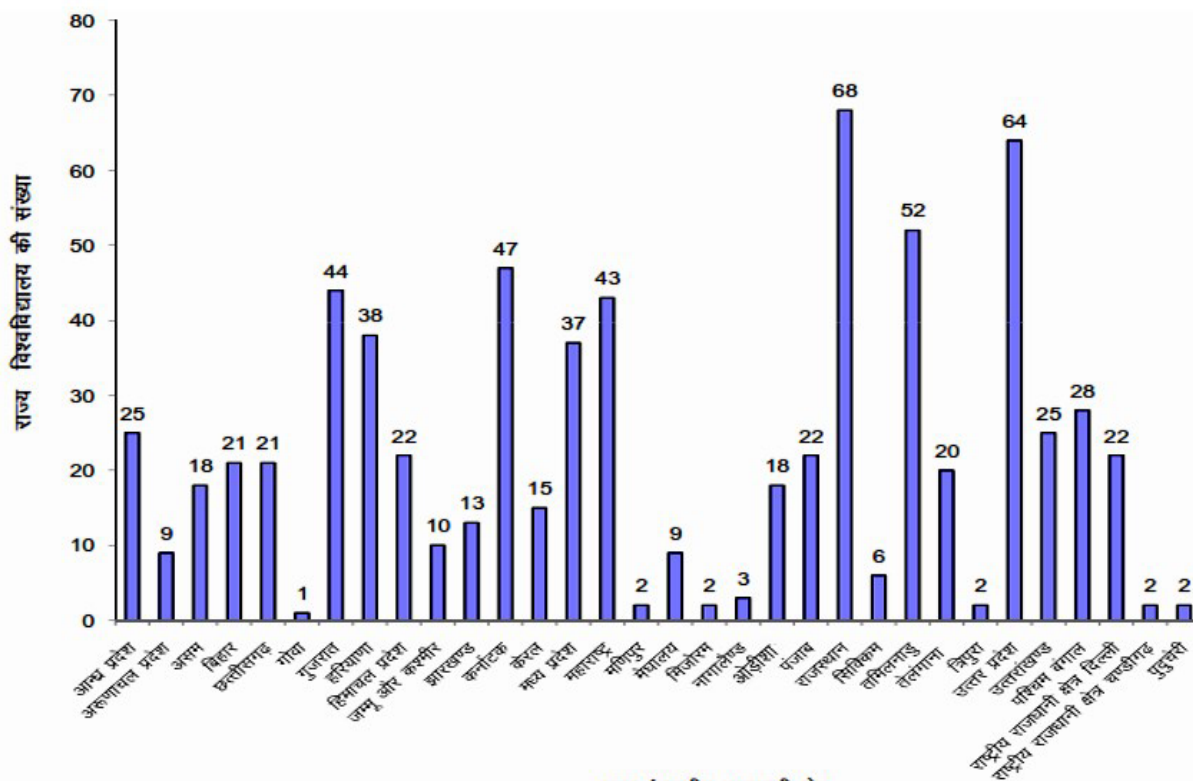
तालिका संख्या 03

क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					
		कुल	केन्द्रीय	राज्य	निजी	सम	अन्य*
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	20	05	25	20	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	09	01	-	07	01	-
3.	असम	18	02	12	04	-	-
4.	बिहार	21	03	12	-	02	01
5.	छत्तीसगढ़	21	01	12	08	-	-
6.	गोवा	01	-	01	-	-	-
7.	गुजरात	44	01	24	17	02	-
8.	हरियाणा	38	01	14	17	06	-
9.	हिमाचल प्रदेश	22	01	04	17	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	10	02	07	-	-	01
11.	झारखण्ड	13	01	07	03	02	-
12.	कर्नाटक	47	01	23	09	14	-
13.	केरल	15	01	12	-	02	-
14.	मध्य प्रदेश	37	02	18	14	03	-
15.	महाराष्ट्र	43	01	20	01	21	01
16.	मणिपुर	02	02	-	-	-	-
17.	मेघालय	09	01	-	08	-	-
18.	मिजोरम	02	01	-	01	-	-
19.	नागालैण्ड	03	01	-	02	-	-
20.	ओड़ीशा	18	01	12	03	02	-
21.	पंजाब	22	01	08	11	02	-
22.	राजस्थान	68	01	20	39	08	-
23.	सिक्किम	06	01	-	05	-	-
24.	तमिलनाडु	52	02	22	-	28	-
25.	तेलंगाना	20	03	15	-	02	-
26.	त्रिपुरा	02	01	-	01	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	64	05	25	23	10	01
28.	उत्तराखण्ड	25	01	10	10	04	-
29.	पश्चिम बंगाल	28	01	21	05	01	-
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22	05	06	-	11	-
31.	संघ क्षेत्र चण्डीगढ़	02	-	01	-	01	-
32.	पुदुचेरी	02	01	-	-	01	-
कुल		711	46	329	205	128	03

* अन्य में राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान हैं।

स्रोत : यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 2 (च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या



स्रोत : यूजीसी 0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

उपरोक्त चार्ट का अध्ययन करने के पश्चात यह पता चलता है कि—

- आंध्रप्रदेश, गोवा तथा चंडीगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं,
- उ.प्र. तथा एन.सी.आर. ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सबसे अधिक 5-5 विश्वविद्यालय हैं।
- राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक 68 तथा
- 64 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ उ.प्र. इस सूची में दूसरे स्थान पर है।
- इसके बाद तमिलनाडु में कुल 52 राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हैं।
- विश्वविद्यालयों की संख्या के दृष्टिकोण से गोवा सबसे पिछड़ा राज्य है जहाँ मात्र 1 विश्वविद्यालय है।



तालिका संख्या 04

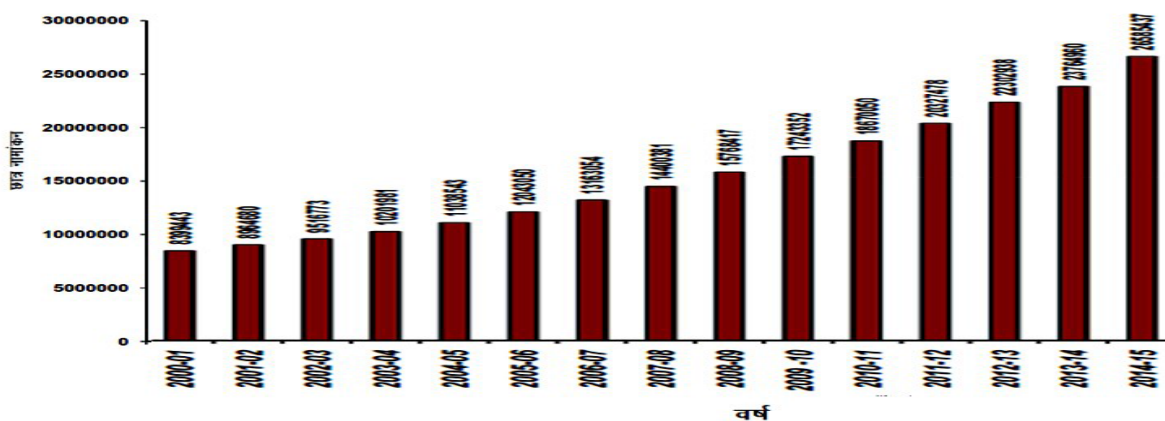
2000 - 2001 से 2014-2015 के दौरान संपूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशत
2000-01	8399443	348836	4.3
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009 -10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12*	20327478	1657428*	8.9
2012-13*	22302938	1975460*	9.7
2013-14*	23764960	1462022*	6.6
2014-15**	26585437**	2820477**	11.87**

स्रोत : यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

तालिका संख्या 05

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र नामांकन में वर्ष-वार वृद्धि: 1984-85 से 2014-15



स्रोत : यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

उपरोक्त तालिका तथा रेखाचित्र के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सत्र 2004-05 में कुल 110.38 लाख छात्रों का नामांकन हुआ।

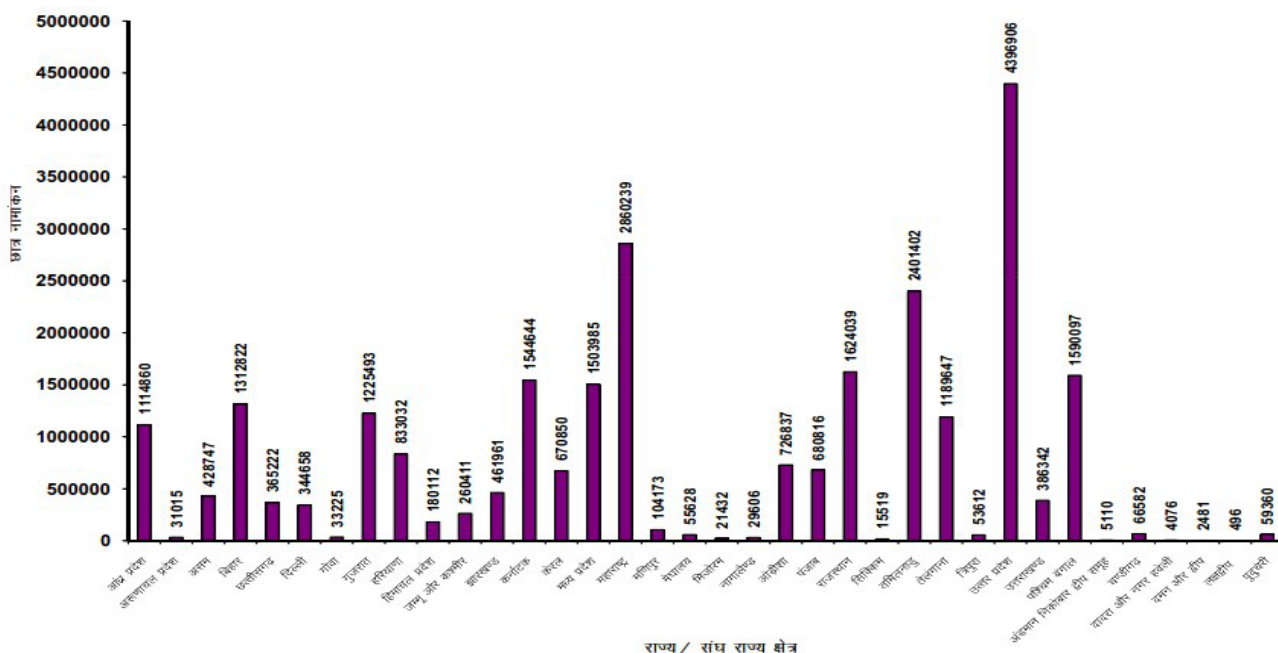
- जिसमें पिछले सत्र 2003-04 की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी।
- वही सत्र 2012-13 में छात्रों की संख्या 9.7 प्रतिशत बढ़ गयी।



- इसके अगले ही सत्र 2013-14 में छात्रों का पंजीकरण लगभग 3.1 प्रतिशत घटकर 6.6 प्रतिशत हो गयी।
- वही 2014-15 में छात्रों का पंजीकरण 265.85 लाख हो गई जो अबतक का अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर (11.87 प्रतिशत) हैं।

तालिका संख्या 06

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राज्य-वार छात्रों का नामांकन : वर्ष 2013-14*

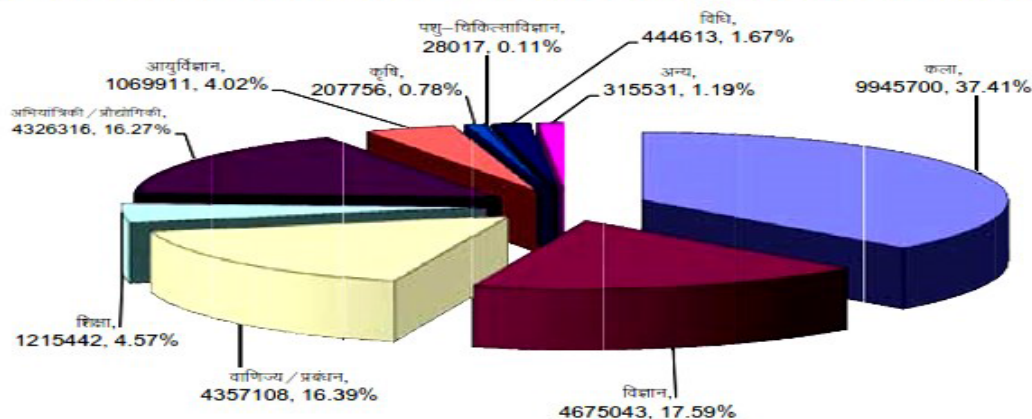


स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

उपरोक्त आँकड़ों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट पता चलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जहाँ सर्वाधिक 4396906 नामांकन सत्र 2014-15 में हुआ है। वही उसका बाद सर्वाधिक नामांकन वाला राज्य महाराष्ट्र है जहाँ सत्र 2014-15 में कुल नामांकन 28,60,239 हुआ है तथा सबसे कम नामांकन वाला राज्य लक्षद्वीप है जहाँ कुल नामांकन 496 हुआ। वही लक्षद्वीप ऐसा राज्य है जहाँ कुल नामांकन का 71.17 प्रतिशत नामांकन केवल महिलाओं का है।

तालिका संख्या : 07

वर्ष 2014-2015 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संकाय-वार छात्रों का नामांकन

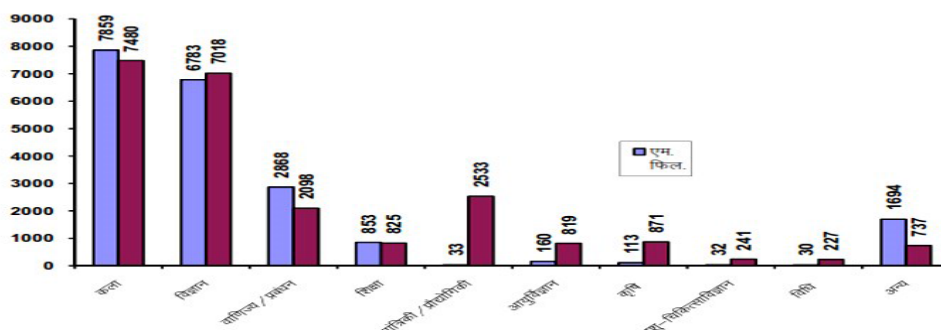


स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

उपरोक्त पाई चार्ट का विश्लेषण करने के पश्चात हमें पता चलता है कि सत्र 2014-15 में छात्रों का कुल नामांकन 265.85 लाख में से 37.41 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 17.59 प्रतिशत वाणिज्य/प्रबंधन विज्ञान में 16.39 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार कुल नामांकन में से 71 प्रतिशत छात्र कला, विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंधन के तीन संकायों में था, जबकि शेष 29 प्रतिशत व्यवसायिक संकायों में थे, जिनमें से प्रौद्योगिकी/अभियंत्रिकी में सर्वाधिक 16.27 प्रतिशत थी तथा सबसे कम प्रतिशत पशु-चिकित्सा में 0.11 प्रतिशत था। इस प्रकार, जैसा कि संकायवार संवितरण से स्पष्ट है कि पेशेवर की तुलना में गैर पेशेवर नामांकन का अनुपात लगभग 1:3 रहा है।

तालिका संख्या : 08

वर्ष 2013-2014 के दौरान प्रदत्त की गयी एम.फिल. एवं वाचस्पति (पीएच.डी.) उपाधियों की संकायवार संख्या (563 उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आंकड़े)



स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15



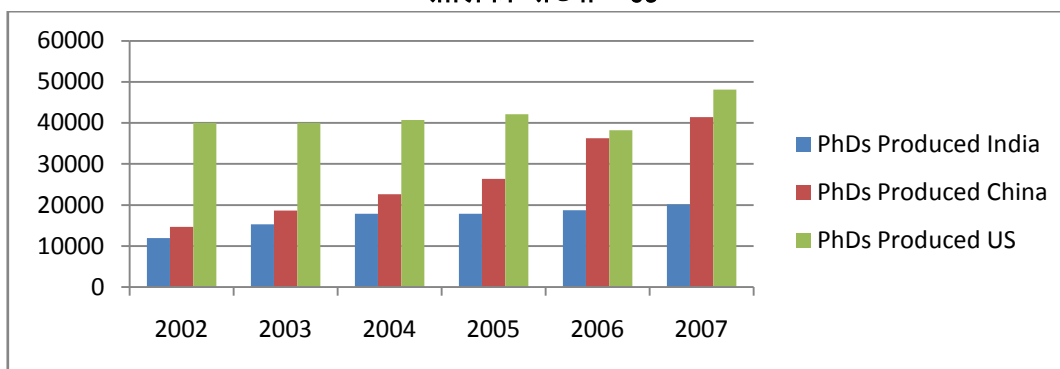
उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के पश्चात यह पता चलता है कि सत्र 2012-13 में शोध उपाधियों की संख्या 20275 तथा सत्र 2013-14 में शोध उपधिकारियों की संख्या बढ़कर 22849 हो गयी। यानि की लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदत्त शोध उपाधियों में कला संकाय में प्रदत्त उपाधियों की संख्या सर्वाधिक 7480 थी, उसके बाद विज्ञान संकाय का स्थान रहा जिसमें 7008 उपाधियाँ प्रदान की गयी।

कुल प्रदान की गयी उपाधियों में इन दोनों संकायों में 63.45 प्रतिशत पीएचडी उपाधियाँ प्रदान की गयी। वाणिज्य/प्रबंधन संकाय में 2098 प्रबंधन उपाधियाँ की गयी।

पेशेवर संकायों में अभियंती व प्रबोधक संकायों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिनमें 2533 शोध उपाधियाँ प्रदान की गयी हैं इसके बाद कृषि में 871 तत्पश्चात शिक्षा संकाय में 8025 शोध उपाधियाँ प्रदान की गयी तथा सबसे कम शोध उपाधि विधि संकाय में प्रदान की गयी जिसकी संख्या 227 है।

तालिका संख्या : 09



स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

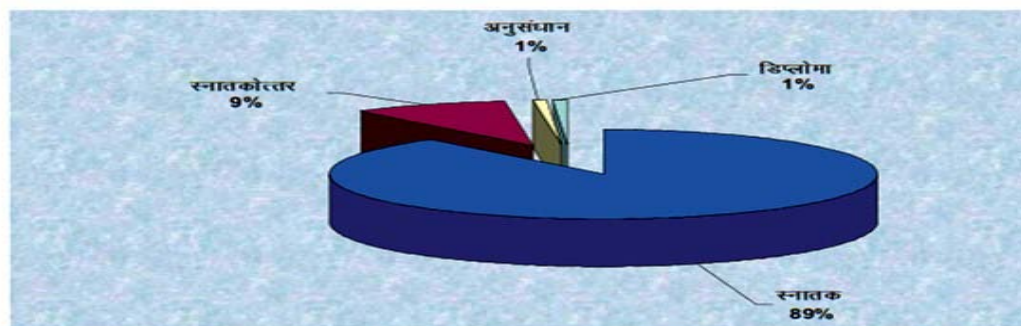
2002 से 2007 तक दिए गए पीएचडी उपाधियों की विभिन्न राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन :

उपरोक्त चित्र का अध्ययन करने के पश्चात यह पता चलता है कि सन् 2002 में भारत का शोध आउटपुट 11974, चीन का 14704 तथा अमेरिका का 40024 था जो भारत से 28050 अधिक था। जबकि चीन से भारत मात्र 2732 थी।

वही 2007 में भारत की स्थिति 20131 थी तथा चीन में 41464 था जो भारत से लगभग दो गुना हो गया जबकि अमेरिका में शोध आउटपुट में केवल 8098 की ही वृद्धि हुई। अर्थात चीन केवल 5 वर्षों में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की।

तालिका संख्या : 10

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में स्तर-वार छात्रों का नामांकन 2007-2008



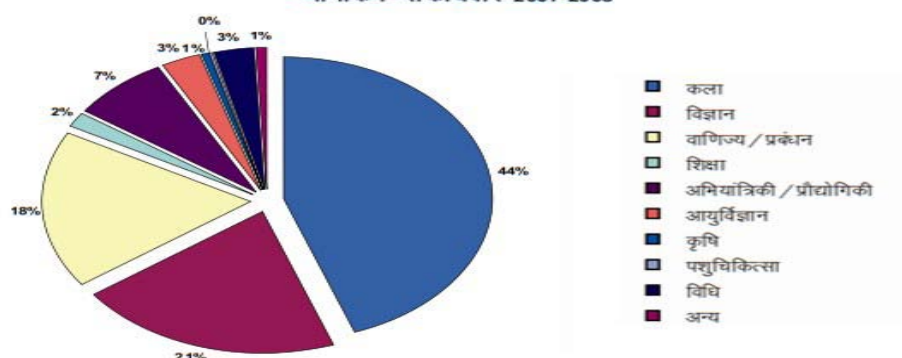
स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि —

- कुल नामांकित छात्रों का 89 प्रतिशत छात्र स्नातक स्तर पर ।
- स्नातकोत्तर स्तर पर 09 प्रतिशत छात्र नामांकित हुए।
- वही शोध स्तर पर यह मात्र घटकर 1 प्रतिशत हो जाता है।
- जो डिप्लोमा स्तर में 1 प्रतिशत नामांकन के बराबर है।
- इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि भारत में शोध की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

तालिका संख्या : 11

नामांकन—संकायवार 2007-2008



स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

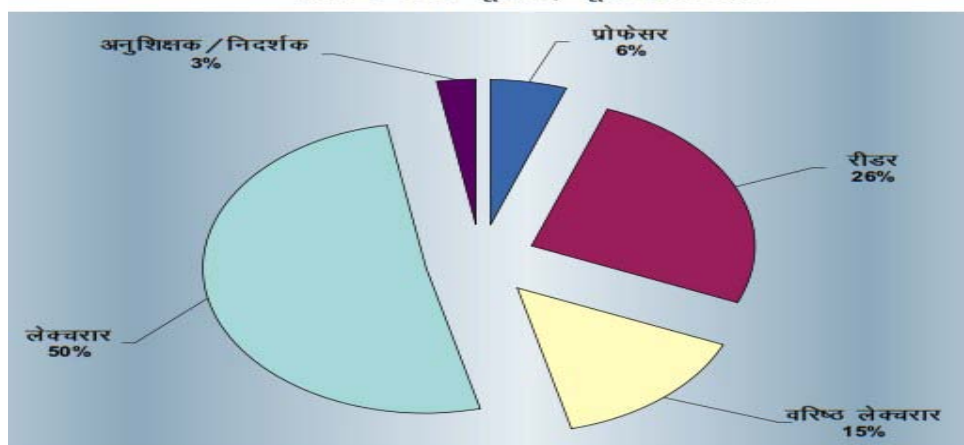
उपरोक्त चार्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट पता चलता है कि —

- सत्र 2007-08 में सबसे अधिक कला वर्ग में नामांकन हुआ।
- जो कुल नामांकन का 44 प्रतिशत है।

- उसके विज्ञान वर्ग में 21 प्रतिशत हैं।
- जो कला वर्ग में हुए नामांकन का लगभग 50 प्रतिशत हैं।
- वाणिज्य एवं प्रबंधन में विज्ञान वर्ग में हुए कुल नामांकन 3 प्रतिशत घटकर 18 प्रतिशत हो गया था।
- शिक्षा संकाय में कुल नामांकन का 2 प्रतिशत हैं जो वाणिज्य संकाय के कुल नामांकन का 10.11 प्रतिशत हैं।
- वही पशु चिकित्सा संकाय में कोई भी नामांकन नहीं हुआ है।

तालिका संख्या : 12

शिक्षण स्टाफ यूटीडी/यूसी 2007-2008



स्रोत : यूजीसी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि—

- सत्र 2007-08 में विश्वविद्यालयों में कुल अध्यापकों में 50 प्रतिशत प्रवक्ता थे
- जबकि प्रो संख्या कोल अध्यापक की तुलना में मात्र 6 प्रतिशत थी
- वही वरिष्ठ प्रवक्ता की संख्या 15 प्रतिशत तथा रीडर की संख्या 26 प्रतिशत थी

निष्कर्ष :

उपरोक्त आकड़ों के अध्ययन व विश्लेषण से प्रतीत होता है कि—

- आजादी के समय भारत की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उस समय भारत में कुल 20 विश्वविद्यालय एवं 500 महाविद्यालय, 361.09 मिलियन लोगों पर थी तथा आज स्थिति यह है कि 1201 मिलियन जनसंख्या पर 711 विश्वविद्यालय, 40760 महाविद्यालय हैं जो यह दर्शाते हैं कि आजादी के



लगभग 70 वर्षों बाद भी संस्थाओं में वृहद् रूप से वृद्धि हुई है फिर भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती गयी।

- नामांकन के दृष्टिकोण से देखा जाये तो सत्र 1950–51 में छात्रों का नामांकन 397 तथा सत्र 2011–12 में छात्रों का नामांकन 23327 (प्रति 1000) हो गया।
- जो यह दर्शाता है कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी है।
- विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति बहुत ही विषम है।
- दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जबकि आंध्रप्रदेश, गोवा और चड़ीगढ़ जैसे प्रदेशों में एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है।
- यदि शिक्षक छात्र अनुपात की दृष्टिकोण से देखा जाये तो स्वीडन जैसे छोटे देश की स्थिति बहुत ही अच्छी है जहाँ पर केवल 9.5 छात्र पर एक अध्यापक है वहीं भारत में 24 पर एक है जो प्राप्त आकड़ों में सबसे निम्न है।
- अमेरिका की स्थिति दूसरे स्थान पर है जहाँ पर 3.6 छात्रों पर एक अध्यापक है।
- शोध के दृष्टिकोण से देखा जाये तो 2005–07 के मध्य सबसे अधिक शोध (41464) चीन में हुए हैं।
- चीन की तुलना में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि यदि भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है तथा हमारा निर्धारित लक्ष्य 2017 तक जी0ई0आर0 को 30 प्रतिशत लाना है तो जी0डी0पी0 का कम से कम 5 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर व्यय करना होगा तथा मात्रात्मक शिक्षा को बढ़ावा न देकर गुणात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय।

सुझाव :

- आर0टी0ई0 एक्ट को स्कूली शिक्षा से बढ़कर उच्च शिक्षा तक करना चाहिए किन्तु उच्च शिक्षा में यह अधिनियम अनिवार्य न हो कर मुक्त होनी चाहिए।
- शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
- उच्च शिक्षा पर जी0डी0पी0 का कम से कम 5 प्रतिशत धनराशि व्यय किया जाना चाहिए।
- शिक्षक छात्र के बीच अनुपात को कम करना चाहिए।



Research Inspiration

An International Multidisciplinary e-Journal

(Peer Reviewed, Open Access & Indexed)

www.researchinspiration.com

Email: researchinspiration.com@gmail.com, publish1257@gmail.com

ISSN: 2455-443X

Vol. 1, Issue-IV

Sep. 2016

Impact Factor : 4.012 (IIJIF)

- शिक्षको को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए।

संदर्भग्रन्थ सूची :

- यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2005—06
- यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2007—08
- यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2013—14
- यू0जी0सी0 वार्षिक रिपोर्ट 2014—15
- एमडीआरडी.जीओवी.इन
- जनगणना 2011